**Central Universities (Amendment) Bill, 2023 (Discussion not concluded)**

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नं. 20 - केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR):** Hon. Speaker, Sir, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to move:

?That the Bill further to amend the Central Universities Act,

2009, be taken into consideration.?

Hon. Speaker, Sir, I would like to express that the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 is the proposal for amending the Central Universities Act of 2009 for setting up of Sammakka Sarakka Central Tribal University in the State of Telangana.

**16.20 hrs** (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

If the House recalls, I would like to state that 13th Schedule to the Andhra Pradesh Recognition Act, 2014, that is, no.6 of 2014, *inter alia,* provides that the Government of India shall take steps to establish one Central Tribal University in the State of Telangana.

Then, establishment of the Central Tribal University in Telangana is definitely obligatory under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Union Cabinet in its meeting held on 3rd October, 2023 has approved the proposal for establishment of the University in Telangana.

The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 provides for establishment of a Central University and a Central Tribal University in Andhra Pradesh also. They gave the land and everything in due time. A Central University and a Central Tribal University in Andhra Pradesh is functional with effect from 05.08.2019.

Later on, the site selection was delayed and ultimately, the Telangana Government has given the site in Mulugu District. The State Government has offered 335.04 acres of land. The University of Hyderabad prepared the detailed project report for

the University and as per the detailed project report, the project cost is Rs. 889.07 crore. The project will be completed in two phases of three years and four years.

Very nicely, the name of that University has been kept Sammakka Sarakka Central Tribal University. Our visionary leader Prime Minister Narendra Modi-led Government is always very eager to complete its work 100 per cent. Our Prime Minister always thinks deep and works in the root. The story of nomenclature, the naming of the Central Tribal University, is also very much emotional. The mother and daughter Sammakka and Saralamma, commonly known as Sarakka, are believed to be manifestations of Adi Parashakti who will save and protect the tribal communities of Telangana. To give the rightful honour to the tribal communities of Telangana, the name has been given to the University as the Sammakka Sarakka Central Tribal University. This University will provide facilities for research in tribal art, culture, tradition, language, medicinal systems, customs, forest-based economic activities etc.

Hon. Chairperson, Madam, I would like to invite all the hon. Members to have a positive discussion. I beg your permission to start the discussion on the Bill.

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

**SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):** Hon. Chairperson, Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 which was introduced in the Lok Sabha on 04.12.2023. It aims to amend the Central Universities Act, 2009.

The Bill seeks to establish a Central Tribal University in Telangana which will be known as Sammakka Sarakka Central Tribal University. The main focus is on enhancing the access, ensuring quality of higher education, fostering research facilities and promoting advanced knowledge in tribal art, culture, customs and technology for the tribal population across India.

Madam, this is a very welcome move and we support the Bill so that the necessary Tribal University is established in Telangana. It will take care of the regional aspirations. Having a Tribal University will foster the tribals to get access to education, research, preserve our culture, increase access and quality of higher

education, and promotion of higher education and research. So, we welcome this Bill and we stand in support of the Bill.

At the same time, I would like to highlight a few things which we have seen arising in multiple areas where we have Tribal University and so on. The first thing which I see is there has been a gross violation of reservation rules. If you take the case of Indira Gandhi National Tribal University Act, the Adivasi enrolment which used to be around 80-90 per cent in 2013, very unfortunately, has come down to mere 7.5 per cent in 2023 under the NDA Government. If you see, there is a drastic drop in the Adivasi students studying in the Tribal University. One of the main reasons is because the admission to this University is linked to the Central University Entrance Test, CUET, which is really inaccessible to tribal students.

मैडम, मैं समझाना चाहता हूँ कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में क्या समस्या आती है, इनके एनरॉलमेंट में क्या समस्या आती है। आदिवासी तब बनते हैं, जब उनके पास प्रिमिटिव ट्रैट्स होते हैं, इकनॉमिकली बैकवार्ड होते हैं, सोशली बैकवार्ड होते हैं और इनमें एक शायनेस ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है, जो एक आदिवासी की पहचान होती है। When we study in the primary education or the higher education, हमने विभिन्न राज्यों में देखा है कि जो ड्रॉपआउट्स होते हैं, उनको भाषा समझ में नहीं आती है। एक आदिवासी की भाषा अलग होती है। कुई भाषा होती है, सोरा भाषा होती है। ओडिशा में जैसे उडिया भाषा होती है, तेलंगाना में तेलुगू होती है। हर जगह डिफरेंट-डिफरेंट भाषाएं होती हैं। हमने देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉपआउट का मैन रीजन यह है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है। उसके लिए कई सारे इंटरवेंशन हुए हैं कि गांव में स्कूल्स को कैसे बनाना है।

अब हम जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट सीबीएसई करिकुलम के अंतर्गत है और जो एग्जाम सेन्टर्स हैं, these are very far off. If I take an example, एक आदिवासी क्षेत्र पहाड़ों में या गांवों में होता है। इसलिए एक शहर में जाकर, हैदराबाद में जाकर एग्जाम देंगे तो वह उनके लिए बहुत दूर होता है। उस वजह से उनका एनरॉलमेंट भी कम होता है। यह मैन चीज है, जिसे हमें देखना है। केवल बिल्डिंग बनाने से सब कुछ नहीं होता है। हम ऐसा माहौल कैसे बनाएंगे? आदिवासी लोग की जो कला संस्कृति है, उनकी भाषा है, उसके साथ एंटान्गल करके ये कैसे पढ़ाई कर सकते हैं?

मैडम, मैं एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण देना चाहता हूँ। यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा के कोरापुट में है। वर्ष 2009 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। आज 10-15 साल हो गए हैं, जो पैसे इनिशियली यूपीए के टाइम हम लोगों ने दिए थे, वे पैसे वापस हो गए हैं। अब उस यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं हैं। तीन साल पहले मैंने पार्लियामेंट में उनके स्टाफ के बारे में मुद्दा उठाया था। वहां के टीचर रिक्रूटमेंट का मुद्दा भी उठाया था। प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 23 थीं, लेकिन पोस्टेड जीरो थे। एसोसिएट प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 43 थीं, लेकिन पोस्टेड सिर्फ एक था। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 88 थीं, लेकिन पोस्टेड 16 ही थे। ये तीन साल पहले की बात है,

मैंने जीरो ऑवर में भी यह मुद्दा उठाया था। मैं मंत्री जी से भी मिला था। तब कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि क्या प्रोग्रेस हुई? प्रोफेसर की पोस्ट्स 23 थीं, उनमें से 14 पोस्ट्स के लिए

एडवरटाइज किया गया, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया गया, लेकिन सिर्फ दो पोस्ट्स पर ही भर्ती हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया गया, लेकिन जीरो भर्ती की गई। इसलिए भर्ती करने में कुछ तो प्रॉब्लम है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? जब भर्ती नहीं हो रही है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज़ को लेकर संस्था चला रहे हैं। उसमें रिजर्वेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज के लिए उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। They do not come under the purview of reservation. यहां पर यह हालत है। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा, कोरापुट के लिए मैं बार-बार डिमांड करता आ रहा हूँ कि कुछ फंड्स दे दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। We demand allocation of funds to the Central University, Odisha to build infrastructure. We do not need loan. We need grants through Higher Education Financing Agency, HEFA. हमें HEFA के अंतर्गत एजुकेशन चाहिए।

दूसरा, मैं ड्राप आउट्स के बारे में कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स हैं, nearly 13,000 students have dropped out. इसमें क्या होता है? उनकी ऐक्सेप्टिबिलिटी नहीं होती है। जो मेन स्ट्रीम में आते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। यह बड़ी दु:खद बात है कि जब सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय के लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करें, तो इनके ड्रॉप-आउट्स को देख कर क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।

एक एससी-एसटी सेल होता है। They talk to the counsel. जो आदिवासी और एससी वर्ग के बच्चों की काउंसिलिंग करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने अभी पिछले साल ही स्थापित किया है। बहुत सारे सुसाइड्स की घटनाएं आईआईटीज में घटी हैं। उनमें एससी-एसटी वर्ग के लोग ही होते हैं। हमें ये सभी चीजें देखनी पड़ेगी। केवल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, इको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब आप ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो मैं यह आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो करिकुलम होता है, जो रिसर्च होती है, वह ट्राइबल कल्चर के ऊपर हो। इंडिया में 800 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। उनकी जो विभिन्न कल्चर्स हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए? हमारी जो शैली है, जो हमारा डांस है, जिसे हम धीमसा कहते हैं, ये सभी चीजें कैसे की जाए? आप इन सभी पर रिसर्च करें, ताकि लोगों को पता चले की ट्राइबल कल्चर क्या होता है, उनकी आईडेंटिटि, उनकी आईडेंटिटि क्या होती है? उसको बचा कर कैसे रखना चाहिए?

मैडम, यह बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, लेकिन केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। हमें पूरा ट्राइबल इको सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़ें, हमारी संस्कृति, भाषा और कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ एक क्वालिटी एजुकेशन आदिवासी बच्चों को कैसे दे पाएंगे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री धर्मेन्द्र जी यहां नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय के लिए पिछले दो सालों में सब कुछ हो गया है, लेकिन उनका दस्तख्त पेंडिंग है। हमारे जयपुर के निवासी बार-बार यह कह रहे हैं कि केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर की स्थापना कब की जाएगी? हम लोगों ने बहुत मुश्किल से केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर के लिए लैंड एक्वायर किया है। सारे फॉर्मलिटीज पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर का इनऑगरेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है, जो बहुत दुखद बात है। हमें आशा था

कि धर्मेन्द्र प्रधान जो ओडिशा के मंत्री होंगे, वे खास कर कोरापुट और जयपुर को देखेंगे, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जवाब में केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर के बारे में भी कुछ अपडेट दें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री सुनीता दुग्गल **(**सिरसा**):** सभापति महोदया, बहुत**-**बहुत धन्यवाद। As regards the Central Universities (Amendment) Bill, 2023, in the Central Universities Act, 2009, जो प्रिंसिपल एक्ट था, उसमें क्लॉज 3 एफ के बाद क्लॉज 3 जी को इंसर्ट किया गया है। इसके अंतर्गत एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। जिसका नाम सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि यह जो यूनिवर्सिटी बन रही है, इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पूरा तेलंगाना रहेगा। इसमें भारत की मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकती है। इसके साथ-साथ इसमें रिसर्च की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसको सीरियल नम्बर 17 पर रखा गया है। तेलंगाना में है। सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से पूरे तेलंगाना स्टेट को लाभ मिलेगा। यह मुलुगु जिले में स्थापित किया जा रहा है।

सभापति महोदया, 4 अक्टूबर, 2023 को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 में कसके। मैं इसके लिए एचआरडी मिनिस्टर, आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जब इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी और उसको आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इन्डोर्स किया। मोदी जी ने लिखा कि ?The setting up of the Sammakka Sarakka Central Tribal University will be a game changer for the youth of Telangana. It will also deepen understanding of tribal culture as well as encourage innovation?.

आदरणीय सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मैनडेट प्राप्त किया। जहां पर बहुत ज्यादा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है।

इसके साथ-साथ राजस्थान में भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। हालांकि तेलंगाना में हमारी तरक्की हुई है, हम 1 से 8 पर पहुंचे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा कि अगर हम तेलंगाना में सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी के बिल को नहीं लेकर आएं। फिर भी हम उस बिल को लेकर आ रहे हैं, यह दिखाता है कि हमारी सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं**?** ?सब का साथ हो, सब का विकास हो, सब का विश्वास हो और सब का प्रयास हो।? इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि इसका नाम सम्मक्का-सरक्का क्यों रखा गया?

सभापति महोदया, उसके पीछे एक सुंदर कहानी है। सम्मक्का-सरक्का मां-बेटी हैं और यह माना जाता है कि जो परा शक्ति अम्बा हैं, ये उनका अवतार हैं।

?या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥?

आपको मालूम है कि तेलंगाना में मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो साल में एक बार सम्मक्का-सरक्का मेदाराम जतारा निकलती है। यह कहा जाता है कि जो ट्राइबल कम्यूनिटी है, उनका यह सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु अलग-अलग राज्यों से भाग लेते हैं। चाहे वे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड से हों, इन सभी राज्यों के ट्राइबल कम्युनिटी के करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। इसे कुम्भ मेला भी कहा जाता है। जो जनजातीय समुदाय है, इसको उसका कुम्भ मेला भी कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण उस मंदिर के पास में ही करवाया जा रहा है, जिससे पूरे विश्व के अंदर जो ट्राइबल दैवीय शक्तियां हैं, उनको पहचाना जा सके, समुदाय के अंदर जनजागरण हो और समुदाय को यह लगे कि उनका भी कोई सम्मान है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

आज हमारी प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी जनजातीय समुदाय से आती हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक बने तो वह हमारी एनडीए की सरकार में बने। अगर दलित समुदाय से कोई राष्ट्रपति बने हैं तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को अपनी सरकार में बनाया है। अब जो जनजातीय समुदाय से महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, वह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बनी हैं। इससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार किस तरह से सब को साथ लेकर चलने वाली है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वह देश के अंदर केवल चार जातियों को देखते हैं और उन्हीं के उत्थान से ही देश का उत्थान होगा? नारी, युवा, किसान तथा गरीब। इनके उत्थान से ही हमारे देश का उत्थान होगा।

आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोगों ने सुबह-सुबह जाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। मुझे लगता है कि नारी, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर किसी ने काम किया है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। उसके बाद अगर इन सब को कोई आगे लेकर चला है तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।

एजुकेशन के बारे में बाबा साहेब ने कहा था? ?Educational endowments and institutions for higher education are the stepping stones in the upward march of our race?. इसी तरह से मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। अभी जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल आया था, इसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह से नौ सीटें ट्राइब्स के लिए रिजर्व की हैं। उसके लिए भी मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि नाम में क्या रखा है? अब ये कहें कि आपने इसका नाम सम्मक्का-सरक्का क्यों रख दिया? नाम से सम्मान होता है। उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी माता जी का नाम कुसुम जी हैं। अगर वह अपनी माता जी को कुसुम जी कहकर बोलें या मां कहकर बोलें तो दोनों में कितना अंतर है। इसलिए ये बार-बार कहते हैं कि आप नाम बदल देते हैं, नाम में क्या रखा है? नाम में सम्मान जुड़ा हुआ है। आज इसी समाज को सम्मान देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम सम्मक्का-सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया है।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह पढ़ाते-पढ़ाते इस संसार से विदा लें और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था? ? Education is the most powerful weapon which you can use to change the world?. अगर हमें दुनिया या संसार को बदलना है तो हमें इंस्टीट्यूशंस को जगह-जगह पर खासकर हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके लिए जगह-जगह पर स्थापित करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदया, इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थीं। वह एक साड़ी पहनकर चलती थीं, तो दूसरी साड़ी अपने साथ लेकर चलती थीं। इसका कारण यह है कि वह कई किलोमीटर दूर जाकर, जहाँ पर वह बच्चियों को पढ़ाती थीं, उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फुले जी ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें उनके ऊपर जगह-जगह पत्थर फेंके जाते थे, कहीं पर उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था ताकि वे बच्चियों को न पढ़ा सकें, लड़कियों को न पढ़ा सकें। इसलिए वे एक साड़ी पहनती थीं और दूसरी साड़ी हाथ में लेकर जाती थीं। जब पहली साड़ी बिल्कुल खराब हो जाती थी, तो वह उसको बदलती थीं। लेकिन उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा।

इसलिए अगर आज हम कहीं पर पहुंच रहे हैं, तो इसमें उन महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहती हूँ, जैसाकि ज्योतिबा फुले जी ने कहा था- *?Cultivation of mind should be the ultimate* aim of human existence. There is no greater deed than the work of education and it is my duty to do it.?

चाणक्य ने इसके बारे में क्या कहा था, मैं वह कहना चाहती हूँ:

?Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.?

अगर उन्होंने ब्यूटी और यूथ से भी बढ़कर किसी बात को कहा था, तो वह एजुकेशन को कहा था।

आदरणीय मोदी जी ने जितना सम्मान नारी को दिया है, जितना सम्मान अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिया है, मुझे नहीं लगता कि उतना सम्मान आज से पहले किसी सरकार ने दिया होगा। अगर उन सरकारों ने इतना सम्मान इन सभी वर्गों को दिया होता, तो आज हमारा देश कब-का विकसित भारत बन चुका होता। सरकार की जो समग्र योजनाएं हैं, अंत्योदय योजना के माध्यम से, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम छोर पर बैठा है, उस तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं कहना चाहूंगी कि पहले के प्रधानमंत्री जी, आपको तो मालूम ही होगा, ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम लोग ऊपर से एक सौ रुपये भेजते हैं, तो केवल पन्द्रह रुपए ही जनता तक पहुंचता है। इसलिए हमारी सरकार ने जन-धन के माध्यम से सभी लोगों के एकाउंट खुलवाए। इसी के साथ, डीबीटी के माध्यम से, हर किसी के पास सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं। फिर भी इस अमृतकाल में हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसको ध्यान में रखते हुए 15 नवम्बर को, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि है, को हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अन्दर रथ चलाया है ताकि यदि कोई ऐसा इंसान रह जाए, जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, तो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और वर्ष 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन सके क्योंकि हमारी सरकार ?सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास? के सूत्र को लेकर चलती है। इसलिए जो समक्का-सरक्का सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।

इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है सभी को साथ लेकर चलने की। इसलिए अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। यह बात मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कह रही हूँः

?मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं,

मंज़िलों से कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं।?

तीसरी बार हमारी जो सरकार बनेगी, उसमें बाकी के जो काम रह गये हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI A. RAJA (NILGIRIS):** I must express my thanks to you for permitting me to say a few words on the Bill namely the Central Universities (Amendment) Bill, 2023.

Madam, reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backwards Classes and backward classes dates back to 1950 or even prior to that. As far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, the reservation started way back in 1943 when Dr. Ambedkar was in the Cabinet in the Viceroy?s Council. As far as reservation for backward classes is concerned, in Tamil Nadu, the State pioneered it in 1920s and 1930s itself. Reservation for backward classes started by the Justice Party.

After Independence, the Viceroy?s Council reservation continued by virtue of the Constitution amendment. Articles 15 and 16 were inserted in the Constitution by expressing the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. As far as Backward Class reservation in the Central Government is concerned, everybody knows that it started during the period of V.P. Singh, the former Prime Minister. The matter whether the Mandal Commission Report which was adopted in the Parliament was constitutionally valid or not was heard in the Supreme Court. The Judges heard the matter. Well known legal personality Dr. Nani Palkhiva argued the case against the Mandal Commission. Prime Minister, V.P. Singh said in Parliament that if the judgement came in Government?s favour, he would die in peace. To that the other side Counsel in the Supreme Court reacted saying that the country may not be in peace if at all the Prime Minister dies in peace. In Tamil Nadu in 1951, reservation for the backward class was given by the Dravidian parties and that was challenged before the Supreme Court. We fought politically against that and got the Constitution Amendment made by the Nehru Government and encomiums were showed on Thanthai Periyar and other Dravidian ideological leaders. So, this is the brief history of how reservation to provide social justice to depressed classes ? whether it is backward classes or OBCs or SCs or STs ? came into existence.

Everybody knows that from the 1940s till the Mandal Commission Report was approved by the Supreme Court, I think that neither the BJP nor the Jana Sangh or the Hindu Mahasabha or RSS never supported reservation. Now, the policy of reservation becomes a compulsion for this Government, not by virtue of convenience.

You are bringing this Bill. I have to appreciate. I will not fail in my duty. But what is the truth? The Mandal Commission judgement came in favour of the Government. V.P. Singh said in this House that he was aware that his Government will be defeated by BJP and others. They had the support of Congress at that time. History cannot be changed. But the quote which was given by V.P. Singh must be born in our minds. It is changing the political climate now. Now, you are also supporting reservation. But the words which were uttered by V.P. Singh in this House were, ?I am only a rocket. I am carrying a satellite, that is the reservation for Backward Classes in the name of Mandal Commission. My duty is to place the satellite in the correct orbit and die. I will die politically, but the satellite will be in the orbit to revolve.? Such a great man V.P. Singh sacrificed his Government for reservation for Backward Classes. Ambedkar did everything for SCs, STs and Backward Classes. Periyar stood for all these things and Dravidian ideology stood firm here. After that, Perarignar Anna, our leader Kalaignar, and still our Muthuvel Karunanidhi Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu are known for social justice.

I am bringing all these things to the notice of the House briefly because at least, whatever be our past, we must not only protect and patronage the reservation, we must really, heartfully involve in the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and BCs. This is because they were oppressed for thousands and thousands of years in terms of education, in terms of economic progress. It is okay that you are bringing this Bill. But already you had set up another such as tribal University in Andhra which is not having its own building. It is running in a transit building. So, what concern do you have towards the SCs and STs? This Bill is being brought to the House out of compulsion and to meet the mandate which was given to you earlier by the Government. But, in spirt, I am having my own doubt about the delivery by the Government.

Is the Government really committed to social justice? You can see it please. One of the worst incidents which is hurting my heart has come to my knowledge. I am serving in the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When the Head of an IIT, Principal or Dean was summoned by the Committee, we

asked some questions. One of the questions was, why frequent suicides were happening among Dalits and OBCs in IIT complexes? The answer which was given by the Head of the IIT was that those students were not able to cope with the curriculum of IIT. I asked them to show me their marks not only in the selection test but also in the entrance examination. With regard to open competition exam, in terms of percentage, it is 98.5 per cent. For backward classes, it is 97.5 per cent. For Scheduled Castes, it is 96.5 per cent or 96 per cent. The difference between open competition and BCs is 1.5 per cent and the difference between OBCs and SCs is one per cent or 1.5 per cent. A man who is lagging behind by one per cent is not committing suicide, but a man who is lagging behind by 1.5 per cent is committing suicide. I wanted to know whether any comprehensive study has been done by the Government. There was no answer.

Then, I put a very sharp question after looking at data. An Economically Weaker Section (EWS) student who got 192 and who belonged to an upper caste, not OBC, SC and ST, was admitted. A man who got 196 was not mentally disturbed and he had not committed suicide. But a man who got only 1.5 per cent less, when it is compared to BCs or SCs, committed suicide. That was the result given before the Parliamentary Committee.

What is the real reason behind this? What is going on? You are all claiming the pride of Hinduism and Hindu. I am also a Hindu under law. But were you like that right from the school up to the Parliament? In some of the areas, school students are having colour watches and colour ties to show their castes. Shri Ritesh Pandey, from the BSP, got a written answer yesterday in the Parliament. How many dropouts are there in the IITs? How many dropouts belonging to OBCs, SCs and STs are there in the IITs? Please see. About 4,596 OBC students, 2,424 Scheduled Caste students, and 2,622 Scheduled Tribes students have dropped out in the last five years from the Central Universities. This is a statement which was laid before the Parliament yesterday. You are opening universities, admitting students, but after the completion of three years, there are dropouts. Is this the real upliftment of OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Not only this, so many other things are happening. It is about professors in the IITs and research institutes. About 27 per cent of reservation might have been given to Backward Classes. But in the IITs, professors have been given only 14 per cent. With regard to Vice Chancellors in the Central Universities, for Scheduled Castes, there is one per cent; for Scheduled Tribes, there is one per cent; and for Backward Classes, there is five per cent. What has happened? How will the students who are studying in the universities, and the

people who are working as Assistant Professors have the courage that they can deliver? A sense of courage is important. Ambedkar said, ?Where is the caste?? You cannot identify my caste in the Parliament by seeing my face. Nobody can say that I am a Dalit, or he or she belongs to the Backward Class by seeing the face. Ambedkar said that caste is not a barbed wire and caste is not a wall of bricks which can be pulled down in one second. It is a notion in your mind. It will create a notion in your mind by identifying a person?s caste. Unless and until this notion is uprooted from the mind, equality will not come. Have you made any single attempt to remove this notion from the minds of the people in India against those who are belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes? No.

I can accuse you. I can charge you. In the name of religion, do not project caste. Do not use your tool to promote caste identity. Caste Census is something different. It is for providing social justice in terms of reservations in jobs. But promoting caste for politics is always dangerous. That is being promoted by you. I can accuse. You are entitled to reply.

Madam, what kind of injustice is taking place here? The representation of people from SC/ST/OBC is very low in higher teaching positions. According to the answer given by this Government in this House, Delhi University had 526 reserved category vacancies in March of this year. Out of 526 vacancies, 123 vacancies are for Scheduled Castes, 61 vacancies for Scheduled Tribes, 221 vacancies for OBC, 86 vacancies for EWS and 42 vacancies are for PH category. In addition to this, 5000 teaching positions are lying vacant in Central Universities. Out of the 5000 posts, 4000 posts are reserved for OBC/SC/ST. None of these posts were filled. Not a single attempt was made to fill these vacancies till this day. But you are introducing this Bill for a separate university. You wanted to say something through this House but you are doing something else which is in the opposite direction.

Madam, I have come across through another exercise which was done by some magazines for Ekalavya schools. All these schools were in bad shape without due and appropriate amenities. Another awkward incident took place which has appeared in the press last month. One upper caste student had an SC roommate in the IIT. He strictly asked the Scheduled Caste roommate not to touch and pollute his belongings. The SC roommate had to take a semester off to deal with this kind of casteist bullying. This was the quote available in the newspaper. This is ragging. Has it come to the notice of the Central Government? What type of measures were taken to remove all these inequalities in the higher educational institutes? These

are all the issues that are there before this Government. If at all you want to say that this Government wanted to have a casteless society to be united in the name of Hindutva in real sense, please give due attention. Do not think that making laws and bringing Bills alone will help build an egalitarian society.

With these words, I conclude.

**SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH):** Madam, today, on the death anniversary of Shri Baba Saheb Ambedkar, I would like to start by quoting him.

?I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved.?

Madam, I thank you for allowing me to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. This Bill has a noble intention and I am happy that the Government have brought this legislation. But, why this Government is bringing this legislation after ten years is because it was recommended in Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Bill intends to establish a Central Tribal University named after the legendary mother-daughter duo Sammakka Sarakka, the duo who fought furiously against all odds for their community?s well-being. The topic is very close to my heart. On the very first day of this Winter Session, I asked the Government?s intention on the issue of a wide range vacancies related to SC/ST/OBC in many Government institutions.

**17.00 hrs**

Today, while speaking on this Bill, I remember Shri Rohith Vemula, a Dalit Ph.D student and his tragic death. I am reminded of his words and I quote: ?The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing.? These are not my words. These were the words of Shri Rohith Vemula. These were his last words.

It is extremely sad that as a society, we have collectively failed to establish equality and deliver social justice. We cannot afford to lose more Rohith Vemulas. In fact, I want to ask this Government a question. Why have they decided to bring this legislation now? Why did the Government announce setting up of the Central Tribal University in Telangana during the State election? I think everybody knows the answer.

पिछले दिनों में इस देश में दलितों, आदिवासियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में देश के सभी लोग जानते हैं। मैनडेट मिलना अलग बात है, लेकिन दलितों, आदिवासियों के दिलों में झाँकना, उनके दर्द को समझना कुछ और बात होती है।

आज हम इसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि crimes against tribals are increasing year after year. Just in two years from 2020 to 2022, it has increased nearly by 22 per cent. We are most concerned about this Government?s ignorance towards SCs, STs, OBCs in educational institutions. About 13,626 students belonging to SC, ST and OBC categories are studying in the most prestigious institutions like IITs, IIMs, and Central Universities throughout the country. There has been a large dropout rate among them in the last five years.

I think the Minister is taking a note of it. Tragically, 32 students committed suicide everyday between 2019 and 2021. This is not a good picture. But as a parliamentarian, as a human being and as an Indian citizen, it is very concerning and alarming to me.

Shockingly, about 24 per cent of individuals of the secondary level find themselves among those who tragically take their own lives. Similarly, 80 per cent of the students of middle-level education and nearly 60 per cent of higher secondary-level education are the faces of this alarming reality.

The Government is bringing a Central University Bill for Tribals. It is a very good step. आप एकलव्य मॉडल को भी लाये, एकलव्य मॉडल पर नए-नए स्कूल्स बने। Till date, 38,000 vacancies are still there in Ekalavya Schools. Out of 740 Ekalavya Schools, only 401 schools are operational and only 58 per cent teachers are there.

आज पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्य मंत्री ?कन्या श्री? के थ्रू 78 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रही हैं। यूनाइटेड नेशन्स ने इसको रिकग्निशन दिया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि अगर हम नींव को ही सही से नहीं रखेंगे तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए नींव को सही से रखना बहुत जरूरी है।

महोदया, हमारे जो मंत्री डॉ. सुभाष जी हैं, वे बंगाल से आते हैं। वे प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप बंगाल से आते हैं और आपको बंगाल का दर्द समझ में नहीं आता है। बंगाल में एक ही सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, जो विश्व भारती है। यह एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। यहां से देश के पूर्व प्रधान मंत्री पढ़ चुके हैं। यहां से जो लोग पढ़ चुके हैं, उनमें से काफी लोग विदेशों में सेटल्ड हैं। यहां तक कि कुछ लोग इस पार्लियामेंट में भी हैं।? (व्यवधान)

क्या आप सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, क्या आप पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे?? (व्यवधान)

महोदया, यूनेस्को ने विश्व भारती को हेरिटेज का स्टेटस दिया है। वहां के वाइस-चांसलर ने कवि गुरु रविन्द्रनाथ जी का नाम नहीं लिखा।

उसके बाद उन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का नाम लिखा है। आप बताइए कि कोई दाढ़ी रखने से रविंद्र नाथ टैगोर नहीं बनता है। आपने रविंद्र नाथ जी का अपमान किया है। यह बंगाल का अपमान है। ? (व्यवधान) यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं, पूरे देश और विश्व का अपमान है। ? (व्यवधान)

डॉ**.** सुभाष सरकार**:** माननीय सभापति जी, ये गलत कह रही हैं। ? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मुझे बोलने दीजिए। ? (व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार **:** आप गलत कह रही हैं, ? बोल रही हैं। ? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** उसके बाद विश्व भारती में हर साल पौष मेला और वसंत उत्सव होता है। ? (व्यवधान)

**DR. SUBHAS SARKAR:** You are telling *??* (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** इन्होंने पौष मेला और वसंत उत्सव को बंद कर दिया।? (व्यवधान)

डॉ**.** सुभाष सरकार **:** आप यह ? बोल रही हैं। ? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैडम, मैं आपसे संरक्षण मांग रही हूं। ? (व्यवधान) मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ? (व्यवधान) यह क्या बात है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैडम, वे खड़े-खड़े ?बोल रहे हैं। ? (व्यवधान) मुझे क्यों नहीं बोलने देंगे? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपको कहाँ मना कर रहे हैं? आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैं एक महिला हूँ और एससी घर से आती हूँ, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ऐसा मत करो। आप आराम से बोलिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैडम, विश्व भारती के प्रांगण में हर साल जो पौष मेला होता है, जहां पर बहुत संगीत होता और जहां पर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, वहां पर विश्व भारती के वाइस चांसलर पौष मेला करने नहीं देते हैं। वसंत उत्सव नहीं करने देते हैं। वे सब कुछ अपनी मन-मर्जी से करते हैं। ईवन स्टूडेंट्स के साथ बहुत

खराब तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स हमारे राज्य के आदिवासी मंत्री को कहते हैं कि उनको पैर के नीचे, जूते के नीचे रखते हैं। यह है इनका आदिवासी दर्द, यह इनका आदिवासी प्रेम।

मंत्री जी, आप यह सब भूल जाइए, आप बंगाल से आते हैं और बंगाल के लिए सोचना चाहिए। मैडम, इन्होंने तारकेश्वर में मेरे केंद्रीय विद्यालय की नींव तक नहीं रखी, जिसके लिए सरकार ने ज़मीन दी है। मैडम, ममता बनर्जी की सरकार ने ज़मीन दे दी, फिर भी इन्होंने तारकेश्वर का केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया।

मैडम, खड़े-खड़े पार्लियामेंट में झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। देश के लिए काम करना पड़ता है। जीत तो हर कोई जाता है, लेकिन देश का दिल जीतना पड़ता है। यही बात बोल कर मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आपका धन्यवाद।

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** Thank you, Madam Chairperson for allowing me to speak on this important Bill. Before I say anything on this subject, I wish to put this on record that I am a Member of the Board of Private Deemed Universities. So, let this go on record.

Madam, the Bill to establish a Central Tribal University in Telangana under the name of Sammakka Sarakka, there is nothing against this Bill and we, the YSR Congress Party, wholeheartedly welcome it. This will give self-respect and educational facilities to tribal students across Telangana.

Before I go into the topic of this Tribal University, I want to touch upon the topic of AP Reorganisation Act under which this Tribal University is being established. The erstwhile State of Andhra Pradesh was divided in 2014 and the AP Reorganisation Act had come in. Under that Act, many institutes were promised to Andhra Pradesh. This was promised to Telangana. Now, it is being established after 10 years. Likewise, many institutes were promised to Andhra Pradesh. In the last 10 years, IIT, NIT, IIM, IISER, IIITDM, IEP, all of these universities have been started but till now, even after ten years of AP Reorganisation Act coming into force, no institute is working from a permanent campus. Also, a tribal university was planned in Vizianagaram, Andhra Pradesh, but till now this does not see the light of the day. I know this that this subject of medical college or medical education might not come under the jurisdiction of Educational Department but it is related to the Government and this is why I am taking it up. There are 13 new medical colleges that have been proposed by the State of Andhra Pradesh. Three of them including one from my constituency have been sanctioned by the Union Government but

another 13 are still in the process. Our Chief Minister has been kept on writing about the same but nothing has been happening.

Even the Regional Institute of Education had been promised in Nellore by the then Minister, Shri M. Venkaiah Naidu ji who later became the Vice President. But whenever we go and meet the Secretary and Under Secretaries, they keep on saying that it is in the DPR stage. We do not understand for how many years it will be in the DPR stage. Yes, you are now announcing one institution for Telangana. But all these institutions had been announced for Andhra Pradesh in ten years but nothing is moving at the pace it is supposed to move.

Next, I come to the point of funding. Yes, establishing an institute or a university is a very easy thing but funding of the institute and making sure it comes into existence is a completely different thing. That requires a lot of funding. Yes, giving funding for the new ones takes some time but what about the existing ones? There was a RUSA funding in which there were huge cuts in the last three-four years. Almost 31 per cent of the actual budget has been utilised under RUSA in the last two-three years. This is atrocious. This was supposed to be used to actually upgrade the State Government universities so that they can provide better facilities for the students across the States.

Coming to the Higher Education Financing Agency (HEFA), it is a new thing that the Union Government has conjured up and brought in. But this funding has only been given to the IITs and no other institutes are eligible under this. Earlier, there was a grant that was given to the IITs. But now, you are saying that you are not going to give a grant. Instead, you are going to give a loan to the IITs. After they use this loan to build up infrastructure, they have to repay the loan. So, what has happened after the IITs have taken this loan?

माननीय सभापति **:** आपका समय पूरा हो गया। अब आप बैठ जाइए।

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU:** Madam, I have been allotted ten minutes? time. ? (*Interruptions*) I can give you one example. The IIT, Bombay has taken a loan of Rs. 520 crore. The fee has been raised for the students by almost 100 per cent. As they have to pay back this loan, they are collecting it from the students. Instead of grant, you are giving loan. Who is bearing the burden of that loan? It is being borne by the students of this country. So, why is the funding under HEFA being given only to the IITs and that too as a loan and not as a grant? Why can it not be

given to the NITs, Central Universities and State Universities? So, I would request the hon. Minister to answer that.

Madam, I have last two points. When we talk about all these things, they say that they are going to improve the educational facilities in India and invite foreign universities in India. That is the new mantra that the Union Government has been bringing about. There were 4.4 lakh students who were studying abroad in 2021. The number was increased to 7.5 lakh in 2022. It will continue to increase for the next four-five years. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** आप कनक्लूड कीजिए।

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU:** It happened in Korea; it happened in Japan. When the country was developing, it had happened in China also. But at some point, it will come back. But the first thing that the Government has to understand is this. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** कृष्णा जी, आप बैठ जाइए।

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU:** Madam, I have one last point. The Government has to understand that the students who are going abroad are going there not just for education but actually, for their lifestyle as well. The Union Government is talking about Atmanirbhar Bharat in every other industry. But when it comes to universities of this country, they want to outsource the whole thing to the foreign universities. So, I would request the Union Government to relook into it.

Madam, my last point is with regard to the Higher Education Commission of India (HECI). This has been brought about in 2018 so that there will be ?Minimum Government, Maximum Governance?. There will be hand-holding for all the higher education institutes. That is what was promised. But what had happened? In 2015-16, there were 276 State Private Universities and in 2019-20, the number of State Private Universities increased to 407. So, there was an increase of 47 per cent. But when it comes to the Central Universities, in 2015-16, there were only 43 Central Universities and in 2019-20, the number of Central Universities increased to 48. So, it increased by only 12 per cent. When the State Private Universities are increasing at the rate of 48 per cent, the Central Universities are only increasing at the rate of 12 per cent. ? (*Interruptions*)

Now, coming to the deemed-to-be-public universities, which are under the Central Government, in 2015-16, there were 32 universities and in 2019-20, the number

increased to only 36. ? (*Interruptions*) There is only 12 per cent increase. ? (*Interruptions*) Again, I would say, it is in your hands. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** श्री चंद्र शेखर साहू।

? (व्यवधान)

**SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR):** Thank you Madam for allowing me to speak on the Central University (Amendment) Bill 2023 on behalf of my party, Biju Janata Dal. Under the leadership of our party leader and honourable Chief Minister Naveen Patnaik, many things have been done for development of tribals in Odisha, be it about education, safety and social condition of tribals or be it about the culture of tribals and maintenance of their places of worship.Chief Minister Naveen Patnaik has set-up Special Development Councils in tribal dominated districts through which arrangements have been made for education of tribals and protection of their religion and culture. Highest provisions have also been made for them in the Budget.This Bill has been brought today due to the obligation made after Andhra Pradesh reorganization. The obligation was for setting up of Sammakka Sarakka Central University in Telangana.

Madam, In Odisha, there is a central university in tribal dominated Koraput but it is not a tribal university. It is a central university. The university is not in good condition. The honourable Minister himself several times in his reply has said that there is staff shortage and for this recruitment process is underway. But, the process has been long delayed, many posts are lying vacant and there is a huge vacancy in faculty positions. I request him to give attention to this issue.

As per 2011 census, Odisha has 22.84 percent (one-third) tribal population which constitute 11 percent of India?s tribal population. Among Odisha?s tribals, Gajapati district has more Kondh population. Likewise, there are there are Kondhs, Sauras, Santhals and Ho tribals in Rayagada, Koraput, Balangir, Boudh, Mayurbhanj, Keonjhar, Jajpur, Balasore, Bhadrak, Sambalpur, Jharsuguda, Sonpur, Deogarh, Dhenkanal, Angul, Sundargarh and Kandhamal. Even in coastal districts like Ganjam and Puri, there is tribal population. If we look at the history of freedom struggle in India, then we can find that tribal leaders had a big role in the struggle.

For this, Odisha?s Laxman Nayak and many other tribal leaders are being worshipped today.

Madam, In view of all these and since India?s 11 percent tribal population is in Odisha, it is important to set-up a tribal university in Odisha. So, I request the honourable minister to set-up a tribal university in any tribal dominated district in Odisha. Due to the efforts of our honorable Chief Minister, there is a private institute in Bhubaneswar named Kalinga Institute of Social Sciences. Till date, about 40 thousand tribal children have studied in the institute, starting from kindergarten to graduation. Every year, 3000 students are passing out from the institute. Currently 30000 students are studying there. Under the leadership of honourable Chief Minister Naveen Patnaik, Odisha government is doing everything for safety, culture and religion of tribals. Initiatives are also being taken for tribal museums. So, I request the honourable minister to take efforts for opening a tribal university in Odisha. I on behalf of my party fully support this Bill. Thank you

श्रीमती संगीता आजाद **(**लालगंज**):** सभापति महोदया, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ज्ञान के प्रति महान वैज्ञानिक, मानवतावादी, शिक्षाविद्, विधिवेता, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करना चाहते हैं। खंड-3 जी के तहत सम्मिलित करने के साथ विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी-देवताओं के नाम पर सम्मका, सरक्का, जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया है। सम्मक्का और सरक्का को साहस और बलिदान की देवी के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित विधेयक में आगे कहा गया है कि जनजाति विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे तेलंगाना राज्य तक विस्तारित होगा और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 889.07 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो एक स्वागत योग्य है। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। यह अच्छी बात है कि सरकार इस तरह के विश्वविद्यालय खोल रही है।

लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर विश्वविद्यालय खोल कर भी इन संस्थाओं को चलाने वाले डीन, प्रधानाचार्य, लेक्चरार और एचओडी और अन्य कर्मचारी न तो अनुसूचित जाति के होते हैं और न ही अनुसूचित जनजाति के होते हैं, न अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं।

चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, चाहे मेडिकल कॉलेजज हो, चाहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य के विश्वविद्यालय हों, इन सभी विश्वविद्यालयों में लाखों पद खाली हैं, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। ये पद कई वर्षों से खाली हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास कोई बैकलॉग ड्राइव चलाकर इन रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है? मेरे लोकसभा क्षेत्र में ब्लॉक लालगंज

में मान्यवर कांशीराम जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने मान्यवर कांशीराम साहेब का नाम हटाकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया जो कि बेहद दुखद है। मेरी सरकार से मांग है कि इसका नाम फिर से कांशी राम इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए। इस संस्थान की स्थापना एससी, एसटी विशेष कम्पोनेंट योजना के तहत की गई थी। मैंने इस संस्थान में विजिट भी किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण के अनुपात में यहां किसी पद को भरा नहीं गया है और सारे पदों को आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर भरा गया है। मैं चाहती हूं कि सरकार इसकी जांच कराए।

मेरे जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो कि स्वागत योग्य है। मेरी सरकार से मांग है कि इस विश्वविद्यालय में महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति की स्थापना भी की जाए।

महोदया, देश में एससी, एसटी और ओबीसी के संस्थानों की स्थापना विशेष कम्पोनेंट योजना के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के फंड से की जाती है, लेकिन इन संस्थानों में जो भर्तियां की गई हैं, वे आउटसोर्सिंग से है। मेरा सवाल है कि क्या सरकार इन संविदा और आउटसोर्सिंग द्वारा भर्तियों में आरक्षण लागू करेगी?

महोदया, इससे पहले की सरकारों में, जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, चाहे डिप्लोमा, आईआईटी, मेडिकल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता था तो शून्य बैलेंस पर एडमिशन होता था, लेकिन अब मोटी रकम जमा करने के लिए कहा जाता है। गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र एकमुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं जमा कर पाते इसलिए ड्रॉपआउट रेट बढ़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं, जिस प्रकार माननीय बहन जी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-12 में शून्य बैलेंस में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों का एडमिशन दिया जाता था, उसी प्रकार वर्तमान सरकार एक नई योजना लाए ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का जो ड्रॉपआउट रेट बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आ सके।

महोदया, मैं एक और अनुरोध करूंगी कि एससी, एसटी और ओबीसी विश्वविद्यालयों,

आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को सरकार जल्द से जल्द बैकलॉग का

ड्राइव चलाकर भरने का काम करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

**डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):** माननीय सभापति जी, आपने मुझे द सैंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इंडिया प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में हब रहा है। यहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और पल्लवी विश्वविद्यालय थे और यहां देश-विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार लगभग 15 लाख बच्चे विदेशों में ऊंची शिक्षा के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि द सैंट्रल यूनिवर्सिटी बिल में सैक्शन 2 के सब-सैक्शन-3 जी में ?कारपोरेट? शब्द का उपयोग किया गया है, उसे बदलकर ?सैंट्रल गवर्नमेंट? कर दिया जाए। महोदया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, इसे सभी देशों ने वर्ष 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया है, लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा सस्ती हो और साथ ही गरीब, आदिवासी, एससी बच्चों को सुविधाएं दी जाएं। मैं द

सैंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2023 में सुझाव देना चाहता हूं कि सैक्शन-2 के सब-सैक्शन-3 में ?प्राइमरी? शब्द को बदलकर ?ओनली? शब्द कर दिया जाए।

महोदया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना विश्वविद्यालय को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 18 सालों से भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय वर्ष 1917 यानी 107 साल पहले ही सत्य की खोज करने की इच्छा सिद्धांत के साथ स्थापित किया गया था, इसकी परिभाषित खोज होनी चाहिए।

जो आज 181.58 एकड़ में फैले हैं या भारतीय उप महाद्वीप का 7 वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन इसको सेंट्रल विश्व विद्यालय का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। यह दुख की बात है। जैसे 2019 में बी+ ग्रेड दिया था, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मंत्री जी बिहार से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए निवेदन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के हम लोगों के निवेदन को स्वीकृत करें। महोदया, नीति आयोग ने 3 सालों के एक्शन एजेंडा में कहा है कि ?The crisis in higher education is perhaps worse than the school system.? नीति आयोग के अनुसार सरकारी विश्वविद्यालय को हाई फंडिंग किया जाए, ताकि वहां सुविधा बढ़े और गरीब बच्चे भी पढ़ें। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस भी है, उनको नमन करते हुए मैं उनके शब्दों को क्वोट कर रहा हूं, जो उन्होंने संविधान सभा में कहा था-

??Knowledge is the basis of human life. To enhance the intellectual capacity of the students; Also, every effort should be made to increase their intelligence.??

अत: उपर्युक्त सुझावों के साथ-साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद):** सभापति महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 शीर्षक वाला यह नया विधेयक, तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जो हमारी बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष केसीआर साहब के साथ हमारे लोक सभा के नेता नागेश्वर राव जी ने भी लंबे समय से मांग रही है। खंड 3 जी को शामिल करने के साथ, विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13 वीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है, जिन्हें साहस और बलिदान की देवी के रूप में जाना जाता है।

महोदया, सदियों से, आदिवासी आबादी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, आदिवासी आबादी में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी, जो कि कुल दर 73% की तुलना में 59% ही है। यह शैक्षिक असमानता उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष को और बढ़ा देती है, क्योंकि आदिवासी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर बेहद कम है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, तेलंगाना में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 7.8% था, जो 18.9% के राष्ट्रीय जीईआर से काफी कम है, इसलिए सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, सामान्य रूप से देश की जनजातीय आबादी और विशेष रूप से तेलंगाना के लिए विशाल क्षेत्रीय और शैक्षिक अंतराल को

संबोधित करेगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय न केवल जनजातीय आबादी की उच्च शिक्षा के लिए पहुंच और बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा, बल्कि उन्नत ज्ञान और अनुसंधान के अवसरों का भी सृजन करेगा। यह आदिवासी कला, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और संस्कृति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति में मदद करेगा।

महोदया, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, जनजातीय भाषाओं, कला और शिल्प पर कक्षाएं प्रदान करना और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में लाना शामिल होगा। यह विश्वविद्यालय जनजातीय आबादी के व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा, इसलिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना न केवल जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का एक अवसर है, बल्कि देश भर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2014 में जब से तेलंगाना राज्य बना है, तब से राज्य सरकार केंद्र से सम्मक्का सरलम्मा जतारा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा देने का अनुरोध कर रही है, सम्मक्का सरक्का जथारा सबसे प्रसिद्ध आदिवासी त्योहारों में से एक बन गया है। विश्व भर से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला भी जाना जाता है। अत: इसे राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में 23 जिले बने हैं। 23 जिलों में नवोदय विद्यालय की हमने बड़ी लंबी मांग रखी है, लेकिन अभी तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं दिया गया है।

उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी मांग है, उसके लिए आप काम करें। मैं आपसे यथाशीघ्र विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित **(**पालघर**):** धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पहले, देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये संस्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, इसलिए वे भौगोलिक रूप से आबादी की एक श्रृंखला को कवर करने में सक्षम हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। मैं देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में सरकार ने सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को किफायती, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में काफी काम किया है। वर्ष 2014 से सरकार ने नए आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटीज, एनआईटी और एनआईडीज की स्थापना की घोषणा की है। वर्ष 2014 से हर साल एक नया आईआईटी और आईआईएम खोला जा रहा है। वर्तमान में, देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं। इस विकास के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 3.45 करोड़ थी, वह वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3.85 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, मुझे इस सदन के सामने यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के अथक प्रयासों से ही लद्दाख को पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला फॉरेसिंक विश्वविद्यालय और रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय मिला। नया केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है और तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय की स्थापना 889.07 करोड़ रुपये की लागत से की जानी है। नए संशोधन विधेयक के बारे में बात करते समय मेरे लिए राज्य में एक समर्पित आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तेलंगाना में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी पूरे देश से सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, उसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए। वहां जो गोंड ट्राइबल कल्चर है, जैसे जो वर्ली कम्युनिटी है, भील कम्युनिटी है और कोंकण कम्युनिटी है, जिस तरह से तेलंगाना में ट्राइबल में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसी तरह से महाराष्ट्र में, पालघर में, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां एक आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाए। आज 10 वीं और 12 वीं कक्षा में, पूरे हिन्दुस्तान में आदिवासियों के एजुकेशन में जो ड्रॉपआउट है, 10 वीं और 12 वीं कक्षा में ड्रापआउट होने वालों की संख्या काफी बड़ी है।

इसलिए उसको कम करने के लिए पालघर में एक कौशल विकास जैसा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। मेरी मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Madam, I was listening to the hon. Minister while he was introducing the Bill. The Government is bringing this Bill especially on such an important day, the *Mahanirvan Din* of *Bharat Ratna* Dr. Baba Saheb Ambedkar. मैं उनको आदरांजलि अर्पित करती हूं। उन्होंने शिक्षा के बारे में जो कहा है, ?It is education which is the right weapon to cut social slavery and it is education which has enlightened the downtrodden masses to come up the social status, economic betterment, and political freedom?. So, I think that is the whole idea of bringing this Bill today.

I would like to ask the hon. Minister a few questions. I am making a completely academic speech, not political. I would like to make that point very clear because education is a very serious subject. It is not BJP versus NCP. I am standing here as a citizen, as a mother, and also as a person who is keen on education. I have a few pointed questions to ask from the hon. Minister.

In the previous speech, Raja ji spoke about ST, SC, OBC, and their dropout rate. I would add two or three more points to what he suggested. What is going to be the curriculum of this university? My colleague from Andhra Pradesh mentioned that you started this curriculum in Andhra but it was there in some old dilapidated building. I do not want to get into the merits of that. उसको शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। फिर ये जो नए कॉलेज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। You have written about inclusion over here. Why have we started this? We have started this to provide avenues of higher education and research facilities primarily to the tribal population of India. What is going to be the quality of education? Is it going to be

research about the tribals but advanced education? That is my first question. So, how are we going to fund the curriculum and what is the way forward? मुझे याद है कि अटल जी की सरकार के समय सर्वशिक्षा अभियान लाया गया था। वह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी कुमुद बंसल जी थीं। One of the finest officers the Government of India has had is Kumud Bansal ji who started Sarva Shiksha Abhiyan.

उसी समय सरकार ने ?कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। ? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? किसके लिए शुरू की गई थी? It was for tribal girls from standard 5th to 8th. मुख्य बात यह है कि ट्राइबल गर्ल्स के लिए वह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अगर आप उसको हॉस्टल में लाएंगे, नई दुनिया दिखाएंगे, तो वह 5 वीं कक्षा में आ जाएगी, लेकिन उस लड़की का 8 वीं कक्षा के बाद क्या होगा? इस देश में प्रथम इंस्टीट्यूट असर रिपोर्ट रिलीज करता है, which is almost like a Bible for education. Even the Government of India uses ASER reports. ASER report says, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रोग्राम है, उसको 5 वीं से 12 वीं कक्षा तक करना है। And then connect it to these universities. My colleague, Mr. Saptagiri asked, ?How will these children qualify to join?? जो ?कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? है, उसको क्यों न इस यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए? अगर आप इतना बदलाव करना चाहते हैं, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं, why do we not use these debates? It is not to just make कि 70 सालों में क्या हुआ। Let us look forward and give each other some fine suggestions to improve the education to make it equal. That way, only we have the right to take Dr. Baba Saheb Ambedkar?s name. We will have to work that out. Why do you not expand this Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and connect it to all these universities that you are opening? There are many tribal schools and *ashramshalas* pan India. मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं, वहां बहुत अच्छी आश्रमशालाएं हैं। देश में सभी जगहों पर हैं। But what is the quality? Has the Government ever outside of ASER report quantified the quality of education that is provided? I have this opinion, and I am proposing this to the Government. आप सब कहते हैं और आपकी जो लीड स्पीकर सुनीता जी थीं, उन्होंने कहा उनकी सिर्फ चार जातियां हैं। उन्होंने काफी एक्स्प्लेन किया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। I want to take this forward. If you have it only for *jatis*, why are we making separate education systems?

While we are looking forward to artificial intelligence, are we looking at the world? We want to make our children global citizens. So, why are we having such a narrow outlook for these children? मेरे ख्याल से आरटीई मनमोहन सिंह जी की सरकार में लाए थे। 25 per cent children go to private schools on subsidized payment under RTE. वहां पर जाति या धर्म नहीं देखा जा सकता है। If it is an elite school, as we call it, डीपीएस हो या कोई भी बड़ा स्कूल इस देश में हो, उसमें आरटीई की 25 प्रतिशत सीट्स रखी जाती हैं। Why not include these children also in this, so that they come on to the main highway? Why should they be left aside in a tribal school? Why do you remind them every day, तुम ट्राइबल बच्ची हो और

तुमको ट्राइबल ही करना है। Why? In the global world, how will technology help this child? Why not make it inclusive? I am just suggesting; I am not taking away from the intent of the Government. The intent may be very good, but with changing technology, with mobile which has given us so much power in our hands now, why not find a better way right now? Maybe in five or 10 years this idea may become completely obsolete. Why not make this Central University for Tribals as a research institute? ऐसा नहीं है कि ट्राइबल बच्चों को ही ट्राइबल का करना चाहिए, दूसरा भी कोई चाह सकता है कि मैं ट्राइबल के लिए सीख लूं। If you really want to preserve their values, their traditions, why should only a tribal learn Warli painting? Why cannot somebody else who is a wonderful artist can learn Warli painting? Why cannot somebody else learn their languages, their culture, or why cannot somebody else do a scholarship or a Ph.D on tribal life of India and map all of them? I am just making a larger point today. I do not want to repeat points, but I have two or three quick questions. For all the SCs and STs, you have a National Overseas Scholarship Scheme. The reply which the Government has given is that there are restrictions on topics. Here you want the tribal girls or the boys to fly. If you want them to fly and become global citizens, then why is there a restriction on subjects? If you are opening it, आप बड़ा दिल करके खोल दीजिए। Let them fly all over the world. Why can we not give them an opportunity? Why is there a restriction on subjects?

Then again, I want to talk about the stipend given to them. That proposal has been sent by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Committee, but the Finance Ministry has not approved it. What is the allocation? A lot of scholarship allocations are given. Have you given all of them because States do not get these allocations? I think one of my colleagues talked about Eklavya Schools. Has anybody assessed the Eklavya Schools to see what is the quality of education in these schools? It is not quantified anywhere. We have to constantly go back to the ASER report which Pratham does. Pratham is an outsider. You are the real insider. You can take help from Pratham which is a wonderful NGO and improve your Eklavya schools. There is no point in just announcing new lovely schemes when the old schemes are not giving us results that we are looking for. The other thing is about vacancies. I think a lot of people have spoken about dropouts. So, I will not repeat the point. But I would like to ask one more question. Under the New Education Policy, we are looking at making education inclusive, modernizing it using technology, we want our tribal children to be the President of India. As your lead speaker said, she is so proud of her. There are many tribal Members here now, and there have been many in the past also. They earned their merit and have done extraordinarily well. Even Mr. Gavit who just spoke is a highly qualified Member of

Parliament from Maharashtra. We are very proud of him. My question to you is this. UGC is an independent body, according to the best of my knowledge. UGC has come up with a new directive which says, universities should have a selfie point. Now, why should our colleges be looking at selfie points? I send my children to college पढ़ाई करने के लिए। सेल्फी निकालने के लिए बच्चों को नहीं भेजती हूं। It is a very serious thing. UGC decides my child?s future. ? (*Interruptions*) Rudy ji, I would like to expand it since he is asking me. UGC has taken out an order that colleges in India should put up selfie points with the hon. Prime Minister?s photograph in the background. That is the explanation. ? (*Interruptions*) I did not want to say it because I have a very high regard for him. He is not only your Prime Minister; he is my Prime Minister also. So, I was trying to keep this point away. But I really do not send my child to college to learn how to take a selfie? Do not politicize. ? (*Interruptions*) I can table it. ? (*Interruptions*) It is in the news. ? (*Interruptions*) I am happy to yield. ? (*Interruptions*) hon. Minister is replying. ? (*Interruptions*) I am happy to yield. ? (*Interruptions*)

**DR. SUBHAS SARKAR:** Answer will be given in due time. ? (*Interruptions*) Answer will be given in due time. ? (*Interruptions*)

It is not required to be repeated again. It is the Prime Minister?s photograph. Students have been encouraged to serve for the Viksit Bharat. ? (*Interruptions*)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** What is this? He is confirming it. ? (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी **(**सारण**):** आपको क्या तकलीफ है अगर बच्चे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** All I am trying to say is that let us make our education inclusive. That was my limited point. That was the suggestion which I made. I appreciate the hon. Minister also for honestly telling us what the UGC plan was. I am very grateful to you. So, the record is set for the country what the truth is.

Lastly, I would like to quote Mahatma Jyotiba Phule. Even the speaker from the Treasury Bench quoted Mahatma Jyotiba Phule. He comes from the State where I come from. I was fortunate enough to be the only child of my parents, a girl child born out of their choice. Education-wise, I am well qualified. So, I am one of those lucky girl children. I do not call myself a girl child. I was born as a single child to my parents out of their choice. But I was fortunate to be born in a liberal family and married into an even more liberal family where education is very, very forward. So, I would like to quote Mahatma Jyotiba Phule because of whom I stand here today.

He said: ?Without education, wisdom was lost; without wisdom, morals were lost; without morals, development was lost; without development, wealth was lost?. Such thing has happened due to lack of education. So, that is my limited point. If you are making this intervention for the tribals, we welcome that step, we support it. But we should make them global citizens and include them in the new education policy. You should come back with a more detailed and comprehensive Bill to make to more effective. It is my limited choice. Thank you, Madam.

श्री राजीव प्रताप रूडी **(**सारण**):** महोदया, डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारम्भ करता हूं।

सभापति महोदया, यह शब्द सम्मक्का-सरक्का का जो स्वरूप है, उसके बारे में मैंने बगल में बैठकर अपने मित्रों से जानना चाहा कि ये कौन हैं और काफी परिश्रम के बाद मैं यह समझ पाया कि यह आदिवासियों के लिए दर्शनीय और प्रेरणा के प्रतीक थे, जहां आज भी आंध्र प्रदेश में करोड़ों लोग उस स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं। वह स्थान पूजनीय है। सरकार ने वर्ष 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यह विधेयक लेकर आए हैं और यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्राइबल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं और यह स्पष्ट है कि देश में कोई भी विश्वविद्यालय किसी एक समाज के लिए नहीं है। चूंकि यह एस्पिरेशनल है और मुझे लगता है कि सुप्रिया जी इसी को रखने का तरीका अलग से बता रही थीं।

Saying that it is a tribal university is basically to put that as an aspirational university. It cannot confine to a particular section of the society, and that is the vision of the hon. Prime Minister.

मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक जीवन में, एक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा की होती है। हम सब यहां पर बैठते हैं। हम सब सदन में आते हैं। सबसे पहले संस्कार घर में मिलता है, उसके बाद स्कूल में मिलता है, फिर विश्वविद्यालय में मिलता है और उसके बाद अपने जीवन में अपनी संगत के साथ मिलता है। हम अपने प्रारंभिक जीवन के लगभग 15 वर्ष से 18 वर्ष शिक्षा में व्यतीत करते हैं और वहीं से हमारे जीवन की शुरूआत होती है। हमारे जैसे लोग सदन में आते हैं, कागज पलटकर पढ़ते हैं, आपसी संवाद कायम करते हैं, मित्रों से बात करते हैं और भाषण देते हैं तो इसकी ताकत मूलत: उसी शिक्षा से मिली है, जिसकी चर्चा हम बार-बार कर रहे हैं।

मैं इसलिए संदर्भित हूँ, क्योंकि सदन को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास चार प्रोफेशन्स हैं। मैं पेशे से पिछले 30 सालों से राजनीति में हूँ, विधायक हूँ, सांसद रहा हूँ और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ। यह बहुत कम लोगों को पता होगा।? (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा का संदर्भ हमारे जैसे छोटे आदमी से है। मैं जब पांच वर्ष का था, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मेरी माँ ने हमें सिर्फ शिक्षा दी। हम बिहार में बहुत बड़े घर के लोग नहीं थे। मेरी माँ ने हमें एक चीज दी और वह शिक्षा थी। वह पढ़ी-लिखी नहीं थी। अब वह इस धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा दी। अगर आज मेरे पास चार प्रोफेशन हैं, मैं पायलट भी हूँ, वकील भी हूँ, आपके बीच सदस्य भी हूँ और सामान्य रूप से ठीक-ठाक राजनीति भी कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा श्रेय शिक्षा को जाता है। मैं समझता हूँ कि देश में वे चार करोड़

बच्चे जो विश्वविद्यालय में हैं और अगर हम सब यहां पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे हैं तो उन चार करोड़ बच्चों के बारे में कर रहे हैं, जिनके भविष्य के निर्माण की बात है। हमारे जैसे लोग इस विषय में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम दूरदर्शिता और दूरदृष्टि रखें तो बिहार में हजारों वर्ष पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला है, जहां माननीय निशिकांत जी हमें पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ लेकर गए थे। ये सब स्थान हैं। दुनिया में हर कुछ अलग है। हर चीज, जो यहां पर अंकित है, दिखती हैं, वे सब शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। हमारे लिए कुछ विषयों की चिंता यह है कि आज देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय 56 हैं और अब 57 वें विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आखिर में शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों पड़ी? मैं उसका संदर्भ सीधे बिहार की तरफ लेकर जाऊँगा, जहां से महोदया आप भी आती हैं।

मैं पिछले कई वर्षों से अपने विश्वविद्यालयों में और अपने स्थानों पर जाता हूँ, हालांकि मेरी बिहार में स्कूलिंग हुई और फिर मैं पंजाब विश्वविद्यालय में था, जो एक प्रकार से चंड़ीगढ़ की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पश्चात मेरी छात्र के तौर पर राजनीति करने की धरोहर भी वहीं बनी। शिक्षा के माध्यम से ही राजनीति की धरोहर बनी। मैं समझता हूँ कि यह शिक्षा के तहत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन अगर मैं बिहार की तरफ लौट कर आता हूं तो मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। आज बिहार में लगभग 34-35 विश्वविद्यालय हैं। मैं आपको एक संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जहां लगभग 4 लाख विद्यार्थी हैं और किसी भी विद्यार्थी का सेशन 4 साल, 5 साल से कम विलंबित रूप से नहीं चल रहा है। जब सेशन आता है, बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे जैसे नेताओं पर इस बात का दबाव पड़ता है कि हमारी परीक्षा करवा दीजिए। जब विश्वविद्यालयों में परीक्षा की बात की जाती है तो वे कहते हैं कि इनका सेशन कम्पलीट नहीं है और सेशन का मतलब होता है कि सेशन कराने के लिए अटेंडेंस कम्पलीट नहीं है, लेकिन यह जिम्मेवारी किसकी होती है? आप कहीं भी कॉलेज में चले जाइए और वहीं चाहे बिहार का हो या कोटा का हो या देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खचाखच भरे दिखते हैं। भारत में नौकरी के लिए अगर डिग्री की बाध्यता न हो तो बच्चे कम से कम मेरे राज्य में तो कॉलेज में न जाए, वह कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही डिग्री लेकर निकल जाए, क्योंकि सरकार और संविधान की बाध्यता है कि आपको डिग्री लेकर आना है इसलिए कॉलेजों में जाकर परीक्षा देने के लिए वह कहते हैं कि मेरी परीक्षा आ गई है, मुझे डिग्री चाहिए। आखिर इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है। अगर मैं बिहार के बारे में थोड़ा सा कह रहा हूं तो हो सकता है कि देश के अन्य कोने में भी इस प्रकार की समस्या होगी।

**18.00 hrs**

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी। जब कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बच्चे परीक्षा की तैयारी करके यूपीएससी तक जाते हैं, तो आखिर डिग्रीज की महिमा क्या रह जाएगी??(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपका यह भाषण कल भी जारी रहेगा। आप कल बोलिएगा।

सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**18.01 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on*

*Thursday, December 7, 2023/ Agrahayana 16, 1945 (Saka).*

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

**LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

* Not recorded.

** Not recorded.